SHRI N. E BALARAM : I do not know the recommendations made by the Kelkar Committee because I did not go to the Library. I would like to know from the hon. Minister whether by a recent order, prices of some of the life-saving drugs have already been increased. This has created great difficulties for the common people. Will the Government reconsider this question. This is my point.

SHRI J. VENGAL RAO . We are considering this question. We will bring them under the Drug Price Control Order, under Category II. We will reduce the price.

SHRI N E. BALARAM : That is not my point. I said, Government, by a recent order, increased the prices of some of the most important life-saving drugs. Are you prepared to reconsider that question. I am not talking about the whole thing I am talking about the recent Government order

SHRI VASANT SATHE : This question can again be brought up

MR. CHAIRMAN : I have said that we are putting it up for the next week Then, you can put your supplementaries. *(Interruptions)* अगले सप्ताह में इसको ले रहे हैं, तब ले लीजिए। पोस्टपोन कर दिया है सवाल, अगले सप्ताह के लिए।

*126. [*The questioner (Shri Harvendra Singh Hanspal) was absent. For answers,* vide *col* 29, infra]

Outlay on H. B. J. Pipeline

*127. SHRI SHANKER SINH VAGHELA : Will the Minister of PETROLEUM AND NATURAL GAS be pleased to state :

(a) whether the work of laying of HBJ Pipeline has suffered considerable delay, if so, the details of the delay suffered so

(b) what was the total outlay for the laying of this pipeline and how far it is likely to exceed the original estimate; and

(c) apart from Gujarat, what are the other projects it is likely to serve, State-wise ?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS (SHRI BRAHM DUTT : (a) No, Sir. There is no delay in laying of HBJ Gas Pipeline.

(b) The total approved and estimated outlay for the pipeline is Rs. 1700.17 crores and this original estimate is not likely to be exceeded.

(c) Apart from Gujarat, gas will be supplied to the following units in the various States through which the HBJ Pipeline passes.

States	Fertilizer Power Plants
Rajasthan	one Power Plant one Fertilizer Plant
Madhya Pradesh	one Fertilizer Plant
Uttar Pradesh	one Power Plant Four Fertilizer Plants

श्री शंकर सिंह वाघेला चेयरमैन सर, मिनिस्टर साहब ने जवाब दिया है कि इसमें कोई डिले नहीं होगी, वाकई में एसोरेंस चाहेंगा कि डिले नहीं होगी फेजवाइज और सेक्टरवाइज । दूसरा, जिस इण्टेन्सन से पाइप-लाइन को गुजरात में से लेकर गैस ली जा रही है, आयल लिया जा रहा है, छह फर्टिलाइजर प्लांटस के बारे में आपने कहा है । तो क्या आज यह छह फर्टिलाइजर प्लांटस के परपोजलस, जिनमें फर्टिलाइजर प्लांट करने का कहा था, वह स्टेंडस्टील आज भी है ? वर्धराजन हाई पावर कमेटी ने जो यह रिकमण्ड किया है, फर्टिलाइजर प्रोडक्शन करने का कोई मतलब नहीं है, तो यह छह के छह आज भी मौजूद हैं ? इस हिसाब से पाइप-लाइन समय पर पूरी होगी और एस्टी-मेट सही होगा, इसका आश्वासन देंगे ?

श्री ब्रह्म दत्त : मान्यवर, मैंने निवेदन किया कि पाइप-लाइन जुलाई, 1989 में पूरी होनी थी, पूरी होगी । उसमें कोई डिले नहीं होगा और मैं उम्मीद भी नहीं करता कि कोस्ट बढ़ जाएगी । फर्टिलाइजर प्लांट के बारे में जो गुना का फर्टिलाइजर प्लाट है, जहां तक हमारी पाइप-लाइन बन गयी है, उन्होंने थोड़ी गैस लेना शुरू किया है और एक-दो महीने में वे पूरी गैस लेंगे । आवला का फर्टिलाइजर प्लाट और जगदीशपुर का प्लांट, यह आ जाएगा तो फिर समय पर पूरी गैस वहां मिल जाएगी । शाहजहांपुर और बबराला के बारे में थोड़ी दिक्कत है, उसमें काम शुरू होने में थोड़ी देर होती है, जहां तक उनके प्रस्ताव का है, वह अभी भी है, अपनी जगह पर है, देरी उसमें जरूर होगी । लेकिन यह सारा प्रश्न सरकार के विचाराधीन है कि अगर देरी होती है तो हम उस गैस का उपयोग क्या करें, कैसे करें ? हम चाहेंगे कि जो पूंजी उसमें लगी है, उसका उपयोग हो, इस पर पूरा सक्रिय रूप से विचार कर रहे हैं, कुछ ऐसे उपभोक्ताओं की खोज कर रहे हैं, जो इस बीच में ले सकें, हम पावर डिपार्टमेंट से भी बात कर रहे हैं, और लोगों से भी बात कर रहे हैं । तो इस तरह से इसके अधिकतम उपयोग को और जो पूंजी लगी है, उसके उपयोग को, ससाधनों के उपयोग को हम सुनिश्चित कर रहे हैं । जो आपका मूल प्रश्न है, उसमें मैं पूरी तरह आशान्वित हूं कि न इसमें देर होगी और न कीमत बढ़ेगी ।

श्री शंकर सिंह वाघेला सर, गैस के लिए अलग ओ एन. जी. सी. को इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। आयल से जो बाय-प्रोडक्ट होता है तो इस डिले से जो फर्टिलाइजर प्लांट का मामला है, इससे गैस अथोरिटी आफ इण्डिया को कितना नुकसान होगा और क्या भारत सरकार की ऐसी नीति है कि जहां गैस फ्लेअर-अप हो रही है करोड़ों रुपयों की, वहां ही ऐसे गैस-बेस्ड प्लांटस इम्पोज हों, वहां ही गैस का प्रोडक्शन बिजली के लिए हो, जहां-जहां गैस फ्लेअर-अप हो रही है, उसके उपयोग के ऐसे कोई परपोजल गुजरात राज्य से या दूसरे राज्यों से मिले हैं ? क्या वे एज-अर्ली-एज पोसिबल नई इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए देंगे या नहीं देंगे ? और अगर नहीं देते हैं तो कितना नुकसान गैस अथोरिटी आफ इण्डिया को होता है ?

श्री ब्रह्म दत्त : मान्यवर, अगर एक गैस-बेस्ड फर्टिलाइजर प्लांट में देरी होती है तो गैस अथोरिटी को कीमत में प्रतिदिन 37 लाख रुपए का नुकसान होता है और अगर पावर प्लांट को देरी होती है तो करीब 45 लाख रुपए का नुकसान होता है । इसलिए मैंने निवेदन किया कि पूरी तरह से हम इस पर विचार कर रहे हैं । दो तरह की गैस होती है, एक तो तेल के साथ निकलती है, दो तरह की गैस होती है । एक फ्री गैस होती है और फ्री गैस को हम रिजर्व रख सकते हैं और एसोसिएटेड गैस को निकालना पड़ता है । हम कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे उपभोक्ताओं को ढूंढ लें जो इस बीच में गैस को ले लेंगे । फर्टिलाइजर की भी जरूरत होती है । सारा प्रश्न विचाराधीन है । और अगर हम यह सोचें कि जहां गैस जलायी जाती है वहीं फर्टिलाइजर प्लाट लगाए तो बाम्बे हाई में जाकर लगानी पड़ेगी । जहां तक गुजरात का सवाल है . . .

MR. CHAIRMAN : Question Hour is over.

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Inadequate Compensation to the Tribals of Hazaribagh Area

121 SHRI SUKOMAL SEN :

SHRI MOSTAFA BIN QUASEM:

Will the Minister of ENERGY be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the tribals of Hazaribagh area were not paid adequate compensation for their lands, which were leased to the West Bokaro Colliery despite the fact that Colliery is earning a huge profit from the area;

(b) if so, what are the details thereof; and

(c) what steps are being taken by Government to protect the interest of the tribals ?

THE MINISTER OF ENERGY (SHRI VASANT SATHE) : (a) to (c) West Bokaro Colliery is a privately-owned, captive